Review Of Research
ISSN 2249-894X

Impact Factor : 3.1402(UIF)
Volume - 5 | Issue - 2 | Nov - 2015

राजस्थान में प्रथम आम चुनाव तथा लोकतंत्र की स्थापना

हनुमान प्रसाद मीना
व्याख्याता राजनीति विज्ञान , राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर राजस्थान.

प्रस्तावना :

अधिकांश देशी रियासतों में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से लेकर भारतीय संघ में उनके विलीनीकरण तक के इस परिवर्तन काल में मनोनीत मंत्रिमण्डल कार्य कर रहे थे। नए प्रांत के रूप में उदय के लगभग तीन वर्ष पश्चात् ही राजस्थान में प्रथम आम चुनाव हुए। तब तक सभी राजनीतिक दल जनता में अपना–अपना आधार और पैठ बनाकर स्वयं को मजबूत करने की कोशिश करते रहे। इस परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन बंबई में प्रारम्भ हुआ इसमें कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन किया ताकि सम्पूर्ण भारत के साथ–साथ देशी रियासतों में भी उनका संगठनात्मक जनाधार मजबूत बन सके।[1] अब तक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से मान्यता प्राप्त इसकी स्थानीय इकाइयां लोक परिषद अथवा प्रजा मण्डल के नाम से स्थानीय स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहीं थी। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने यह निश्चित किया कि देशी राज्य लोकपरिषद से मान्यता प्राप्त प्रजा मण्डल अब स्थानीय कांग्रेस कार्यसमिति या कार्यकारिणी के रूप में कार्य करेंगी तथा प्रान्तीय परिषद प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के नाम से पहचानी जाएगी। ताकि ये आगे चलकर कांग्रेस के कार्यक्रमों व नीतियों की औपचारिक रूप से अनुपालना कर सके।[2]

दूसरे राजनीतिक दलों ने भी कांग्रेस के समान ध्रूवीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। इससे पहले 1948 ई. में कुछ निश्चित संगठनों जैसे विद्यार्थी परिषद, हिन्दू महासभा, जनाधिकार समिति इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन दलों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया था। इनके ऊपर से 1950 में प्रतिबंध हटा लिया गया।[3]

प्रथम निर्वाचन में भाग लेने वाले राजनीतिक दल

इस चुनाव में कांग्रेस ने सुव्यवस्थिति ढंग से भाग लिया और व्यापक स्तर पर चुनाव प्रचार भी किया। इसके विपरीत अन्य राजनीतिक दल अंसगठित थे और उनका चुनाव प्रचार भी बहुत कम रहा। इन चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशियों के अतिरिक्त मोटे रूप से कुल मिलाकर 12 राजनीतिक दलों ने भाग लिया इसमें–

1	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	7	समाजवादी दल
2	जनसंघ	8	किसान संयुक्त पार्टी
3	कृषक लोक परिषद	9	कम्यूनिस्ट पार्टी
4	रामराज्य परिषद	10	अग्रगामी दल
5	हिंदू महासभा	11	मार्क्सिसिस्ट ग्रुप
6	किसान मजदूर पार्टी	12	शिड्यूल कास्ट फेडरेशन

सम्मलित हैं।[4]

1951 के प्रारंभ तक मतदान की तैयारियां पूर्ण कर ली गयी थीं। मुख्य चुनाव अधिकारी श्री स्वामी प्रकाश चन्द्र की देखरेख में मतदाता सूचियां छपवाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया। राजस्थान में निर्वाचन की अवधि में व्यास सरकार कार्यरत थी और उसने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में महत्वपूर्ण कार्य किया।[5] फरवरी, 1951 में श्री पी.एन. सिंघल को मुख्य चुनाव अधिकारी तथा कार्यकारी प्रमुख, चुनाव सचिव राजस्थान सरकार नियुक्त किया गया। तथा जिला कलेक्टरों को जिला निर्वाचन अधिकारी तथा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया।

राज्य में प्रथम आम चुनावों में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा निर्धारण के लिए भारतीय संसद के अध्यक्ष ने राजबहादुर के संयोजन में एक समिति गठित की थी। इस समिति के सदस्य रामचंद्र उपाध्याय, बलंवतसिंह मेहता, जयवंतसिंह एवं सरदार सिंह थे। समिति ने 23 अप्रैल, 1951 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया।[6]

चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक जिले को उसके आकार के अनुपात में इकाइयों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक इकाई पर निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा एक निरीक्षक नियुक्त किया गया।सम्पूर्ण राज्य को छः जोन में विभक्त करते हुए उनके ऊपर छः अधिकारियों को नियुक्त किया गया। इनमें चार जिला कलेक्टर स्तर के और दो उपखण्ड स्तर के अधिकारी थे। इन्हें प्रत्येक जोन का इनचार्ज नियुक्त किया गया। मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से प्रशिक्षित करने तथा चुनाव से सम्बन्धित कार्य प्रणाली तथा तकनीक को सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों तरीकों से समझने तथा सक्षम बनाने के लिये छदम मतदान तथा मतदान के पूर्व प्रयोग की अनेक स्थानों पर व्यवस्था की गई।[7] राजस्थान को लोकसभा में 20 सीटों पर प्रतिनिधित्व दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधान सभा दोनों के चुनाव साथ–साथ करवाए गए।

निर्वाचन से सम्बन्धित आंकड़े –

मतगणना का कार्य 8 से 15 फरवरी तक चला प्रांत में प्रथम आम चुनाव 4 जनवरी, से 23 जनवरी, के बीच हुए। मतगणना का कार्य 8 से 15 फरवरी तक चला मतदाताओं की संख्या 80 लाख 5 हजार 903 थी।इनके लिए आठ हजार मतदान केन्द्र बनाए गए थे। राज्य के 35 लाख 76 हजार 334 अर्थात 37.22 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया। इन चुनावों में विधानसभा के 160 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 626 एवं लोकसभा के 20 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 74 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। इनमें से विधानसभा के लिये 228 तथा लोकसभा के लिये 25 प्रत्याशी निर्दलीय मैदान में थे।[8] 160 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर कांग्रेस दल के उम्मीदवार निरविरोध चुने गये। जिसमें 2 सीटें सामान्य तथा 5 सीटें आरक्षित वर्ग की थी।626 उम्मीदवार मैदान में थे जिसमे से 153 विजयी हुए तथा 473 चुनाव हार गए।[9] प्रांत के प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस ने लोकसभा के सभी 20 एवं विधानसभा के 156 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव लड़ा। राम राज्य परिषद ने 7 एवं 59, जनसंघ ने 4 एवं 50, कृषक लोक परिषद ने 7 एवं 47, हिंदू महासभा ने 1 एवं 8, किसान मजदूर पार्टी ने 1 एवं 12, अग्रमामी एवं मार्क्ससिस्ट ग्रुप ने 1 एवं 1 तथा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने 1 एवं 1 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किये।[10]

इन चुनावों में कांग्रेस दल को सर्वाधिक सीटे प्राप्त हुई। कांग्रेस को विधानसभा के लिये डाले गए कुल मतों का 39.5 तथा लोकसभा के लिए कुल डाले गए मतों का 41.4 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। रामराज्य परिषद को 0.2, सोशलिस्ट पार्टी को 4.7 एवं 4.3, निर्दलीयों को 27.5 एवं 29.2 तथा अन्य को 9.6 एवं 11.3 प्रतिशत मत क्रमशः विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में प्राप्त हुए।[11]

इन चुनावों में कांग्रेस ने 12 लाख 68 हजार 611, रामराज्य परिषद ने 3 लाख 96 हजार 860, जनसंघ ने 2 लाख 46 हजार 740, कृषक लोक परिषद ने 1 लाख 86 हजार 924, सोशलिस्ट पार्टी ने 1 लाख 17 हजार 299, किसान जनता पार्टी ने 73 हजार 325, हिन्दू महासभा ने 28 हजार 80, किसान मजदूर पार्टी ने 23 हजार 603 और निर्दलीयों ने 9 लाख 24 हजार 165 मत प्राप्त किये।[12]

प्रांत के प्रथम आम चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों को लोकसभा एवं विधानसभा में प्राप्त स्थानों का विवरण इस प्रकार है–

क्र.स.	दल का नाम	विधान सभा (जीते हुए स्थान)	लोक सभा (कुल प्राप्त स्थान)
01	**भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस**	**82 (7 निर्विरोध को मिलाकर)**	**9**

02	कृषिकार लोक पार्टी	7	1
03	राम राज्य परिषद	24	3
04	जन संघ	8	1
05	हिन्दू महासभा	2	—
06	समाजवादी दल	1	—
07	मार्क्सवादी दल	—	—
08	निर्दलीय	35	—
09	किसान जनता संयुक्त पार्टी	—	6
10	अनुसूचित जाति संघ	—	—
11	किसान मजदूर प्रजा पार्टी	1	—
12	फॉरवर्ड ब्लॉक	—	—
	कुल स्थान	160	20

प्रथम विधान सभा–

प्रथम आम चुनाव पूर्ण हो जाने के पश्चात् 3 मार्च, 1952 को प्रांत के प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की। टीकाराम पालीवाल ने मुख्यमंत्री तथा मोहनलाल सुखाड़िया, मास्टर भोलाराम, भोगीलाल पांड्या, रामकिशोर व्यास, नाथूराम मिर्धा एवं अमृतलाल यादव ने मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। रामकरण जोशी मंत्रिमंडल में बाद में शामिल हुए आमेर से निर्वाचित रावल संग्रामसिंह अंतर्कालीन विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किए गए। तत्पश्चात् नरोत्तम जोशी अध्यक्ष एवं लालसिंह शक्तावत उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। राज्य विधानसभा का शुभारंभ 29 मार्च, 1952 को हुआ।[13]

राजशाही के प्रतीकों का लोकतंत्र में विलय

सैंकड़ों वर्षों के वैभवशाली, अनैतिकता से परिपूर्ण, निरूद्देश्य जीवन व्यतीत करने के पश्चात् भारत की स्वतन्त्रता और देश में प्रजातंत्र की स्थापना के झटके से सुशुप्त अवस्था में पड़े राजशाही के प्रतीकों को गहरा झटका लगा। भारत संघ में रियासतों के विलय और एकीकरण ने उनको जागने और जीवन के यर्थात को स्वीकार करने को विवश कर दिया।[14] राजशाही के प्रतीक अधिकांश राजा महाराजाओं ने बदली हुई परिस्थितियों में एक सामान्य नागरिक की तरह अपना स्थान बनाने की चेष्टा की और जो प्रजांतत्र में रहकर भी स्वयं को विशिष्ट मानते रहे वे अपनी कल्पना के महाराजा स्थान में सदा के लिए खो गए।[15]

राजस्थान के गठन के बाद भी प्रांत के शासन में पूर्व रियासतों के राजपरिवारों का बोलबाला बना रहा। कई राजा–महाराजाओं, तथा रानी– महारानियों ने लोकसभा, विधान सभा के चुनाव लड़े और वे न केवल जीते अपितु मंत्री भी बनें और लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते रहे। इनमें प्रथम आम चुनाव में भाग लेने वालों में जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह, डूँगरपुर के महारावल लक्ष्मणसिंह, करौली के बृजेंद्रपालसिंह, शाहपुरा के राजाधिराज अमरसिंह, खेतड़ी के सरदारसिंह, मंडावा ठिकाने के ठाकुर देवीसिंह, बनेड़ा के अमरसिंह, बिजोलिया के राव केसरसिंह इत्यादि सम्मिलित हैं।[16]

1952 के प्रथम आम चुनावों के दौरान अपनी आन्तरिक कलह के कारण कांग्रेस के अनेक बड़े नेता चुनाव हार गये और भूतपूर्व राजा– महाराजा और उनके प्रतिनिधि चुनाव जीतकर लोक सभा और विधान सभा में पहुँचे। जोधपुर नरेश हनुंवतसिंह इन चुनावों में सरदारपुरा क्षेत्र से विधान सभा के लिए और जोधपुर क्षेत्र से लोकसभा के लिये खड़े हुए। विधान सभा सीट पर महाराजा के विरुद्ध राजस्थान के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास खड़े किये गये। यद्यपि महाराजा की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तथापि वे दोनों स्थानों से चुनाव जीत गए तथा जयनारायण व्यास दोनों स्थानों से हार गए। व्यास ने सरदारपुरा व आहोर विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।[17] पराजय के कारण 2 मार्च 1952 को उन्हें अपनी सरकार का त्यागपत्र देना पड़ा । उन्होंने बाद में किशनगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से हुए उप चुनाव में विजय प्राप्त की और टीकाराम पालीवाल के अक्टूबर

1952 में त्यागपत्र देने के पश्चात् 1 नवम्बर 1952 को पुनः राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।[18] प्रथम चुनावों में गोकुलभाई भट्ट, माणिक्य लाल वर्मा, रघुवर दयाल गोयल जैसे कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए एवं पूर्व नरेश एवं उनके द्वारा समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीत कर विधान सभा में जा पहुंचे और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने लगे।

जो भी हो राजतंत्र समाप्त हुआ प्रजातंत्र की स्थापना हो गयी। राजा–महाराजा इतिहास के पन्नों में सिमट गये। आज लगभग 70 वर्षों की अल्प अवधि के बाद भी नयी पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करना कठिन हो जाता है, कि किसी समय यहां चमकीली पोषाकों, हीरे– जवाहरातों से जगमगाती पगड़ियों और सोने चांदी के सिंहासन पर बैठकर राज्य करने वाले राजाओं और रानियों का शासन था।

संदर्भ सूची

1. परिपत्र न. 22, 13 मई, 1948, फाइल न. एफ94/1948 अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद/राजपूताना प्रांतीय सभा/प्रजामण्डल अलवर 90/94, अभिलेखागार बीकानेर।
2. परिपत्र न. 23, 25 मई, 1948, फाइल न. एफ 5/1948 अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद/राजपूताना प्रांतीय सभा/प्रजामण्डल अलवर 90/94, अभिलेखागार बीकानेर।
3. a राजनीतिक विभाग का नोटिफिकेशन (सी.) न. एफ 7(70)/पोलिटिकल (सी)/49 एण्ड न. एफ. 7(188) पोलिटिकल (सी)49 3 फरवरी 1950, राजस्थान सरकार, एक्स्ट्रा आर्डिनरी गजेट खण्ड प्रथम न. 164 4फरवरी 1950

   b राजस्थान गजट एक्सट्रा आर्डिनरी खण्ड प्रथम न. 177, 17 मई 1950
4. रिपोर्ट– प्रथम आम चुनाव 1952
5. प्रकाश पुरोहित – राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम कालीन पत्रकारिता पृ. 210
6. धीरेन्द्र जैन– राजस्थान परिचायिका
7. राजस्थान के प्रशासन पर रिपोर्ट 1951–52 (1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1952) राजस्थान सरकार जयपुर (1954) पृ. 44
8. ए स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ द जनरल इलेक्शन इन राजस्थान, द ब्यूरो, ऑफ स्टेटिस्टिक राजस्थान जयपुर(1952) पृ. 45
9. राजस्थान के प्रशासन पर रिपोर्ट 1951–52 (1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1952) राजस्थान सरकार जयपुर, 1954 पृ.45
10. धीरेन्द्र जैन– राजस्थान परिचायिका
11. ए स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ द जनरल इलेक्शन इन राजस्थान, द ब्यूरो, ऑफ स्टेटिस्टिक राजस्थान जयपुर(1952) पृ. 104
12. के.एल कमल – पॉलिटिक्स इन इण्डियन स्टेट्स पृ. 78–79
13. सुखवीर सिंह गहलोत– राजस्थान का तिथिक्रम पृ. 143
14. जरमनीदास–महाराजा पृ. 398
15. उपरोक्त पृ. 400
16. वर्णमाला, कैलाश एवं मधु – राजस्थान कांग्रेसी उम्मीदवार परिचय पुस्तिका
17. उपरोक्त
18. सत्यदेव विद्यालंकार– धुन के धनी, पृ. 165